RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 285
दि. 16.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

विकसित भारत की दिशा में निर्णायक कदम: वैश्विक नेतृत्व, मजबूत रक्षा और आर्थिक विस्तार का स्पष्ट रोडमैप

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उसकी आर्थिक, सामरिक और वैश्विक भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्पष्ट होती जा रही है। हाल ही में दिए गए एक विस्तृत साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहेगा, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। उन्होंने बजट 2026, मुक्त व्यापार समझौतों, रक्षा आधुनिकीकरण, डिजिटल तकनीक और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए यह संदेश दिया कि सरकार का हर निर्णय दीर्घकालिक विकास और राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बजट 2026 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत के निर्माण की एक ठोस और दूरदर्शी योजना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बुनियादी ढांचे पर 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्ष 2013 की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है। यह निवेश केवल सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका उद्देश्य देश के हर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अल्पकालिक लोकप्रिय फैसलों की बजाय दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए जा चुके हैं, जो भारत के निर्यात और आर्थिक विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन समझौतों के माध्यम से भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिल रही है, जिससे देश के लाखों उद्यमियों

और श्रमिकों को लाभ हो रहा है। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, केमिकल और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए यह समझौते विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भारत की पारंपरिक ताकत रहे हैं और इनसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता, सेवा क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हैं। यही कारण है कि भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक उत्पादक और निर्यातक राष्ट्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री के अनुसार, सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि एक संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सके। रक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत के रक्षा बलों को आधुनिक और सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। बजट 2026 में रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही रक्षा पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे नई तकनीकों, आधुनिक हथियारों और उन्नत रक्षा प्रणालियों को शामिल किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत को दुनिया में एक नई पहचान दी है और यह केवल तकनीकी प्रगति का उदाहरण नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। आज देश के छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार डेटा सेंटर, सुपर-कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना बना रही है, जिससे भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा सके।

प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी निर्णायक है और सरकार ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, जिसमें उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने निजी कंपनियों से अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी मजबूत करने का आह्वान किया। उनका मानना है कि जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे, तभी भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

महिला सशक्तिकरण के विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों और योजनाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में उनका योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत आज आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर अपनी बात रख रहा है। उन्होंने कहा कि देश अब केवल वैश्विक नीतियों का अनुसरण करने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक विकास के कारण नहीं, बल्कि देश की स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।

उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत आज एक "रिफॉर्म एक्सप्रेस" की गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों का उद्देश्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए देश को तैयार करना भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा और विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा।

प्रधानमंत्री के इस साक्षात्कार से यह स्पष्ट होता है कि सरकार का दृष्टिकोण व्यापक और दूरदर्शी है। रक्षा, अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीक, वैश्विक व्यापार और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे सभी क्षेत्रों में संतुलित और रणनीतिक विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह केवल योजनाओं और घोषणाओं का दौर नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन का समय है, जो भारत को एक नए युग की ओर ले जा रहा है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता: सस्ती व्हिस्की और कारों के साथ खुलेगा नए आर्थिक अवसरों का युग

(जीएनएस)। भारत और United Kingdom के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, जिसे Comprehensive Economic and Trade Agreement (सीईटीए) कहा जा रहा है, अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। यह समझौता केवल दो देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे आर्थिक युग की शुरुआत का संकेत है जिसमें व्यापार, निवेश, तकनीक और उपभोक्ता बाजार के नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत में स्कॉच व्हिस्की और ब्रिटिश लग्जरी कारें पहले की तुलना में सस्ती हो सकती हैं, वहीं भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के विशाल बाजार में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा, जिससे भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।

यह समझौता 24 जुलाई 2025 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, और इसके तहत भारत के लगभग 99 प्रतिशत उत्पादों को ब्रिटेन में बिना किसी आयात शुल्क के प्रवेश मिलेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत के वस्त्र, जूते, रत्न-आभूषण, खिलौने, खेल सामग्री और अन्य कई उत्पाद अब ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और देश के विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलेगी। यह कदम भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना और घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना है।

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसके तहत ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क में क्रमिक कमी की जाएगी। वर्तमान में इस पर लगभग 150 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया जाता है, जिसे तुरंत घटाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा और धीरे-धीरे वर्ष 2035 तक इसे 40 प्रतिशत तक लाया जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि भारत में स्कॉच व्हिस्की की कीमतें कम हो सकती हैं और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे। यह ब्रिटिश उत्पादकों के लिए भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंच बनाने का महत्वपूर्ण अवसर भी होगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी यह समझौता बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके तहत ब्रिटेन से आयात होने वाली कारों पर वर्तमान में लागू लगभग 110 प्रतिशत शुल्क को कोटा आधारित व्यवस्था के तहत अगले पांच वर्षों में घटाकर 10 प्रतिशत तक लाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत में ब्रिटिश लग्जरी कारें पहले की तुलना में अधिक सस्ती हो सकती हैं और ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे और बाजार में गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

इस समझौते का लाभ केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारतीय कंपनियों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों को ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे वे वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकेंगी।

SIR प्रक्रिया पर सियासी घमासान, ओवैसी ने उठाए नागरिकता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल

(जीएनएस)। देश की राजनीति में एक बार फिर नागरिकता, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का उपयोग नागरिकों की नागरिकता और उनके मतदान अधिकारों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के लिए खतरा बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ओवैसी ने यह बयान अपनी पार्टी के 68वें पुनरुत्थान दिवस के अवसर पर आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया, जहां हजारों समर्थक मौजूद थे और उन्होंने सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए।

अपने संबोधन में ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत नागरिकों का वोट होता है और यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो वह न केवल

मतदान के अधिकार से वंचित होता है, बल्कि उसकी नागरिकता पर भी संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन किए जा सकते हैं, जिससे वास्तविक नागरिकों के नाम हटने का खतरा बढ़ जाता है। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसके दुरुपयोग की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ओवैसी ने विशेष रूप से यह दावा किया कि इस प्रक्रिया को पहले बिहार में लागू किया गया और अब इसे अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना और महाराष्ट्र में लागू करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि यह प्रक्रिया बिना पर्याप्त पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी के लागू की जाती है, तो इससे लाखों लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अल्पसंख्यक और दलित समुदाय, इस प्रक्रिया से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास कई बार आवश्यक दस्तावेजों की कमी होती है या उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं होती।

अपने भाषण में ओवैसी ने लोगों से विशेष रूप से सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को नियमित रूप से मतदाता सूची की जांच करनी चाहिए और यदि उनका नाम सूची में नहीं है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर उसे सही कराना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रियाओं में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर और कानूनी तरीकों से अपनी आवाज उठाकर किसी भी अन्याय का मुकाबला करना चाहिए।

ओवैसी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों और उनकी भागीदारी पर आधारित होता है। यदि किसी नागरिक को मतदान से वंचित किया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का अधिकार छीनने का मामला नहीं होता, बल्कि यह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का प्रयास होता है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और किसी भी प्रक्रिया का उपयोग इन अधिकारों को सीमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, ओवैसी ने हाल ही में हुए एक विवादास्पद घटना पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें एक मुस्लिम विक्रेता के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में विभाजन और अविश्वास को बढ़ावा देती हैं और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता और सहिष्णुता में है और किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म या पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

ओवैसी ने यह भी कहा कि नागरिकता और मतदाता सूची जैसे मुद्दे अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचें।

सूर्यकुमार की अगुवाई में भारत का विराट विजय अभियान पाकिस्तान पर 61 रन की ऐतिहासिक जीत से 8-1 की अजेय बढ़त

(जीएनएस)। क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और Pakistan के बीच यह भावनाओं, सम्मान और प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाता है। जब भी दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, तो यह मुकाबला केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह करोड़ों दिलों की धड़कनों का हिस्सा बन जाता है। कोलंबो के प्रतिष्ठित आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने एक बार फिर अपने क्रिकेटीय प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 61 रन से हराकर न केवल मैच जीता, बल्कि टी20 विश्व कप इतिहास में अपनी बढ़त को 8-1 तक पहुंचाकर एक नया इतिहास भी रच दिया। यह जीत केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की निरंतरता, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक बन गई है।

मैच की शुरुआत में भारतीय टीम को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही जब युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटके के बाद टीम पर दबाव बढ़ गया था और पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसे समय में जब टीम को एक मजबूत साझेदारी की आवश्यकता थी, तब युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने जिम्मेदारी संभाली और अपनी आक्रामक शैली से मैच की दिशा बदल दी। उन्होंने केवल 40 गेंदों में 77 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, संतुलन और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण दिखाई दिया, जिसने भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान किशन के साथ कप्तान सूर्यकुमार

यादव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 32 रन की संयमित और प्रभावशाली पारी खेलते हुए टीम की पारी को स्थिरता प्रदान की। सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में परिपक्वता का परिचय दिया और यह साबित किया कि वे बड़े मंच पर टीम का नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हैं। उनके अलावा तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने भी क्रमशः 25 और 27 रन का योगदान देकर टीम के स्कोर को मजबूत बनाया। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने केवल चार गेंदों में 11 रन बनाकर टीम को 175 रन के सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।

पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी में सैम अयूब ने तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी को कुछ हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया, जबकि उस्मान तारिक, शाहीन अफरीदी और सलमान आगा को एक-एक विकेट मिला। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों की संतुलित और आक्रामक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह हावी होने का मौका नहीं दिया और टीम ने एक ऐसा लक्ष्य खड़ा किया, जिसे हासिल करना आसान नहीं था।

176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और विपक्षी टीम को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। शुरुआती ओवरों में ही पाकिस्तान ने अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट केवल 13 रन के भीतर गंवा दिए, जिससे टीम पूरी तरह दबाव में आ गई।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके और केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। उस्मान खान ने जरूर 44 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली और टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। भारतीय स्पिन गेंदबाजों अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने मध्य ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और अंततः पूरी टीम 114 रन पर सिमट गई।

यह जीत भारतीय टीम के लिए केवल एक मैच जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इससे पहले भारत ने अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ भी शानदार जीत दर्ज की थी, और पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत के साथ टीम ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सुपर-8 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उतरी है और खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बनकर उभरी है।

टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले हमेशा से रोमांचक और ऐतिहासिक रहे हैं, लेकिन इस जीत ने भारतीय टीम की श्रेष्ठता को और भी मजबूत कर दिया है। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 8-1 की ऐतिहासिक बढ़त हासिल कर ली है, जो इस प्रतिद्वंद्विता में भारत के दबदबे को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, रणनीति और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है।

इस जीत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारतीय टीम का सामूहिक प्रदर्शन रहा। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी, सभी क्षेत्रों में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और यह साबित किया कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्तमान समय में विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। युवा खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन ने टीम को और भी मजबूत बनाया है और भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता का प्रदर्शन किया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि टीम बड़े मुकाबलों में दबाव को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। यह जीत भारतीय क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है और यह दर्शाती है कि आने वाले समय में भी भारतीय टीम विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहेगी।

संपादकीय

शहरी पुनर्जागरण की दिशा में निर्णायक कदम: अर्बन चैलेंज फंड से आधुनिक भारत के शहरों का भविष्य

भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उसकी प्रगति की गति और उसकी विकास यात्रा का स्वरूप काफी हद तक उसके शहरों की स्थिति पर निर्भर करता है। शहर केवल जनसंख्या के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे आर्थिक ऊर्जा, सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक विकास के प्रमुख वाहक होते हैं। जिस देश के शहर सुव्यवस्थित, सक्षम और आधुनिक होते हैं, वही देश वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर पाता है। इसी आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह केवल एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि यह भारत के नगरीय ढांचे को नए सिरे से मजबूत और भविष्य के अनुकूल बनाने का एक व्यापक संकल्प है। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। लाखों लोग हर वर्ष बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की तलाश में शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। शहर अवसरों का प्रतीक हैं, लेकिन इसके साथ ही वे अनेक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। यातायात जाम, जल संकट, प्रदूषण, अव्यवस्थित निर्माण, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, कमजोर जल निकासी प्रणाली और सीमित हरित क्षेत्र जैसी समस्याएँ अधिकांश शहरों की वास्तविकता बन चुकी हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल छोटे-मोटे सुधारों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अर्बन चैलेंज फंड इसी व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम है। इस योजना की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि यह केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहे, बल्कि इसमें वित्तीय अनुशासन और सहभागिता भी सुनिश्चित हो। केंद्र सरकार परियोजनाओं की लागत का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी, जबकि 50 प्रतिशत राशि बाजार से जुटानी होगी और शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था शहरों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करेगी। जब शहर बाजार से निवेश जुटाने में सक्षम होंगे, तो वे अपनी वित्तीय क्षमता को भी मजबूत करेंगे और निवेशकों का विश्वास भी अर्जित करेंगे। यह मॉडल विकास को केवल सरकारी जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे एक साझेदारी आधारित प्रक्रिया बनाता है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना के माध्यम से चार लाख करोड़ रुपये तक की परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। यह निवेश शहरों के बुनियादी ढांचे को एक नई दिशा दे सकता है। बेहतर सड़कें, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन, स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली, मजबूत सीवरेज नेटवर्क, स्वच्छता व्यवस्था, डिजिटल सुविधाएँ और हरित क्षेत्र का विस्तार—ये सभी पहलू शहरों को अधिक रहने योग्य और उत्पादक बनाएंगे। इससे न केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि यह देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति देगा। भारत के शहरों की सबसे बड़ी चुनौती उनका अनियोजित विकास रहा है। कई शहरों का विस्तार बिना किसी दीर्घकालिक योजना के हुआ है, जिसके कारण आज वे बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। नई कॉलोनियाँ बन गईं, लेकिन उनके साथ पर्याप्त सड़कें, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित नहीं हो सकीं। परिणामस्वरूप, नागरिकों को दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्बन चैलेंज फंड इस स्थिति को बदलने का अवसर प्रदान करता है। यदि इस योजना के तहत विकास कार्य दीर्घकालिक दृष्टिकोण से किए गए, तो शहरों की संरचना अधिक संतुलित और सक्षम बन सकती है। यह योजना केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मध्यम और छोटे शहरों को भी शामिल किया गया है। यह एक दूरदर्शी निर्णय है, क्योंकि भविष्य में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे और मध्यम शहर भी उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के नए केंद्र बन सकते हैं। यदि इन शहरों का विकास समय रहते किया गया, तो यह महानगरों पर बढ़ते दबाव को कम करेगा और क्षेत्रीय संतुलन को भी मजबूत करेगा। पर्यावरणीय संतुलन इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि शहरों का विकास इस प्रकार किया जाए कि वे हरित और पर्यावरण-अनुकूल हों, तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होगा। हरित भवनों का निर्माण, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना और जल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना—ये सभी कदम शहरों को स्थायी और टिकाऊ बना सकते हैं।

स्वर्ग के शैतान, कश्मीर घाटी में 35 वर्ष बाद भी बची हुई है विषबेल

> “ मई 2022 में विशेष एनआईए अदालत में यासीन मलिक ने सभी आरोपों को कबूल किया, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां, आपराधिक साजिश और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना शामिल था। 25 मई, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को आतंकवाद को आर्थिक मदद मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन वायुसैनिकों की हत्या का मामला अभी चल रहा है और उसमें यासीन को मृत्युदंड मिलना निश्चित है।

आसी गच्छीए पनुनुय पाकिस्तान, बताव रोस्तुय बतेनियन सान (हमें अपना पाकिस्तान चाहिए। कश्मीरी पंडित पुरुषों के बिना, लेकिन कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ)। – 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कश्मीर के मुसलमानों द्वारा सार्वजनिक पर्चों में की गई घोषणा।

मेरे पिता का देहांत हो गया है, हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार उनकी अस्थियां (फूल) हरिद्वार में गंगा जी में प्रवाहित करने हमें जाना है। आपसे प्रार्थना है हमें हरिद्वार यात्रा की इजाजत दें - मोहन लाल टिक्कू।

उर्दू दैनिक श्रीनगर टाइम्स के 11 दिसंबर, 1990 के अंक में छपा विज्ञापन जिसमें हिंदू परिवार इस्लामी जिहादियों से हरिद्वार जाने की अनुमति मांग रहा है।

कश्मीरी पंडित कायर थे, दगा दे गए, जिन्होंने अपनी मर्जी से घाटी को छोड़ा। उनको कश्मीर में नौकरियां दीं गईं, फ्लैट दिए गए, लेकिन वे काम नहीं करते, जम्मू में ऐश कर रहे हैं- शोपियां से स्वतंत्र विधायक शबीर अहमद कुले का जनवरी 2026 में न्यूज 18 पर बयान। (विवाद बढ़ने पर बयान वापस लिया)

पृथ्वी पर भारत एकमात्र देश है, जहां के देशभक्त नागरिकों को ‘स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र’ में राष्ट्र ध्वज के प्रति वफादारी और धर्मनिष्ठा के कारण अंतहीन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। अपने ही देश में निर्वासन भोगना पड़ा। कश्मीरी हिंदू अपने घर, सेब के बगीचे, खेत, अखरोट और बादाम के पेड़, सब जस के तस छोड़कर आने पर मजबूर हुए।

कश्मीर के मुस्लिम नेता, उन हिंदुओं के मुस्लिम पड़ोसी, उनके मुस्लिम मित्र सब मुंह मोड़कर अपने ही रक्त बंधुओं और मां-बहनों को रोते-बिलखते जाते देखते रहे। किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने उनको बचाया नहीं।

गिरिजा टिक्कू जैसे अनेक लोमहर्षक उदाहरण कश्मीर की खूनी वादियों में बिखरे हुए हैं।

वह पति के साथ कश्मीर के बांदीपोरा नगर में एक स्कूल में प्रयोगशाला सहायिका के नाते काम करती थी। जेकेएलएफ (जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) के कुख्यात मुखिया यासीन मलिक के ‘काफिरों घाटी छोड़ो’ ऐलान के बाद गिरिजा टिक्कू सपरिवार जम्मू आ गई। कुछ दिन बाद उसको श्रीनगर से किसी ने फोन किया कि हालात सुधर गए हैं, तुम आकर अपना वेतन ले जाओ। विश्वास कर वह अपने स्कूल गई। वेतन लेकर अपनी मुस्लिम सहेली से मिलने आई और सोचा वहां से जम्मू वापस आ जाएगी। वहां उसकी सहेली और नागरिकों के सामने जेकेएलएफ के मुजाहिद गुंडों ने उसका अपहरण कर लिया। गिरिजा टिक्कू को इस्लामी दरिंदे अज्ञात स्थान पर ले गए, दुष्कर्म किया, कई दिन बाद जब उसका क्षत-विक्षत शव मिला तो पता चला उसको आरे से जिंदा काटा गया था। हजरतबल श्रीनगर इलाके से नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया गया। उसके साथ कई दिन सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बाद में सड़क किनारे उसका शव मिला। दोनों ही मामलों में किसी के आंसू नहीं बहे, किसी ने इनको मानवाधिकार हनन का मामला नहीं माना। हिंदुओं पर अत्याचार सामान्य और रोजमर्रा की बात मानकर संविधान, सरकार, चुनाव, राजनीतिक उठापटक के दौर चलते रहे। चलती रही पत्थरबाजी, हड़तालें, खूंखार हत्यारे यासीन मलिक की शानदार दिल्ली दावतें और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उसकी मुलाकातें!

25 जनवरी, 1998 (गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले)- कश्मीर के गांदरबल जिले के वंधमा गांव में इस्लामी आतंकवादियों ने एक हिंदू परिवार में भारतीय जवानों के वेश में आकर चाय पी और वायरलेस पर जब उनको बताया गया कि सब हिंदुओं को एकत्र कर लिया है तो उन सबको गोलियां मार दीं, जिनमें दो और चार साल के नन्हे बच्चे भी थे। इससे पहले कि पाठक कश्मीर के हिंदू नरसंहार को भूलें, उनको भारतीय वायुसेना के जांबाज अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर रविंद्र कुमार खन्ना की शोकांतिका से परिचित कराना जरूरी है।

अमृतसर निवासी स्क्वाड्रन लीडर खन्ना 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर के पास रावलपुरा बस स्टैंड पर वायुसेना बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ वायुसेना के अन्य चार कार्मिक भी थे। जेकेएलएफ के आतंकवादी यासीन मलिक के नेतृत्व में वहां पहुंचे और एके47 से वायुसैनिकों पर गोलियां चला दीं। इस भयानक हत्याकांड की कांग्रेस तथा मुफ्ती-अब्दुल्ला शासनों में गवाहियां तक नहीं हुईं। यासीन इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त होने के बावजूद दिल्ली आता रहा, प्रधानमंत्री से मिलता रहा। पुलवामा हमले (14 फरवरी 2019) के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अलगाववादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत यासीन मलिक को 22 फरवरी 2019 को श्रीनगर में हिरासत में लिया गया। अप्रैल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2017 के ‘आतंकवाद को आर्थिक मदद’ मामले में पूछताछ के लिए यासीन मलिक को गिरफ्तार किया और दिल्ली के तिहाड़ जेल ले आई।

मई 2022 में विशेष एनआईए अदालत में यासीन मलिक ने सभी आरोपों को कबूल किया, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां, आपराधिक साजिश और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना शामिल था। 25 मई, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को आतंकवाद को आर्थिक मदद मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन वायुसैनिकों की हत्या का मामला अभी चल रहा है और उसमें यासीन को मृत्युदंड मिलना निश्चित है। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के लौह संकल्प ने यह स्थिति कैसे बदली, स्मृतिविहीन समाज आज इसका अनुमान लगाना भी कठिन मान रहा है। हवा बदली, मौसम बदला, पत्थरबाजों का काला दौर खत्म हुआ, धारा 370 और 35ए का अंधा युग समाप्त हुआ, दो झंडों का चुभने वाला सामंती समय समाप्त हुआ, लाल चौक पर हर दिन हर क्षण राष्ट्रीयता का तिरंगा उत्सव अब आम बात हो गई।

यह अविश्वसनीय सा यथार्थ न पाकिस्तानी आईएसआई को सहन हुआ, न ही उनके कश्मीर में बैठे एजेंट्स को।

नतीजा हुआ पुलवामा हत्याकांड- जिसमें 26 हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर क्रूरता से मार दिया गया। आज भी फारूक अब्दुल्ला तथा कुले जैसे कश्मीरी नेताओं के संवेदनहीन बयान बताते हैं कि घाटी के मुसलमान कश्मीरी हिंदुओं की घरवापसी के प्रति सतही बातें करते रहेंगे परंतु उनके मन में प्रतिरोध जमा रहेगा। घाटी में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाकर, वहां सैनिक कालोनियां स्थापित करके तथा घाटी का एकतरफा जनसांख्यिकी असंतुलन न्याय संगत करने के बाद ही कश्मीर शांति का स्वर्ग बन सकेगा। यह कार्य लौह नीतियों से ही संभव हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं!

फिर भी जारी रहीं साजिशें

1990 में कश्मीर घाटी में इस्लामिक आतंकवादी , एक हाथ में कुरआन और दूसरे में पाकिस्तानी सहायता से पाए हथियारों को सार्वजनिक प्रदर्शित करते थे । उन्होंने कश्मीर घाटी को हिंदूविहीन कर दिया और देश मूक दर्शक बना देखता रहा। नस्लीय नरसंहार के साथ-साथ सांस्कृतिक पहचान मिटाने की इस्लामी साजिशें हिंदू मंदिरों के अपमान और उनको क्षतिग्रस्त करने के रूप में 2006 के बाद भी जारी रहीं - मंदिरों पर कब्जे और तोड़फोड़ के साथ।

1989 से 2014 तक 1,000 से अधिक मंदिर क्षतिग्रस्त किए गए। मैं 35 वर्षों से कश्मीर क्षेत्र में जाता रहा हूं और आतंकवाद पर हजरतबल से रिपोर्टिंग भी की। मैंने वह दौर देखा है जब जम्मू-कश्मीर के हर कार्यालय, विधान सभा और हर नेता- पक्ष तथा विपक्ष के वाहनों पर दो झंडे लगे होते थे - एक भारत का और दूसरा जम्मू-कश्मीर रियासत का। भारत का कोई कानून भारतीय संसद द्वारा पारित होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था, जब तक वहां के राज्य की विधानसभा उसका अनुमोदन न कर दे!

प्रेरणा

सपनों की उड़ान और संघर्ष की शक्ति से जीवन को महान बनाने की प्रेरणा

मनुष्य का जीवन केवल परिस्थितियों का खेल नहीं होता, बल्कि यह उसकी सोच, साहस और कल्पनाशक्ति का परिणाम होता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर उम्मीद की लौ जलाए रखता है, वही असाधारण बनता है। इस सत्य को अपने जीवन से सिद्ध करने वाले महान कलाकार चार्ली चैपलिन का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उनका बचपन अभाव, संघर्ष और अनिश्चितता से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उनके जीवन के शुरुआती दिन अत्यंत कठिन थे। आर्थिक तंगी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उनका संसार उनकी मां और उनके भाई तक ही सीमित था। उनके परिवार को कई बार दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी उनकी मां ने उन्हें एक अनमोल शिक्षा दी—जीवन की सुंदरता केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि मन की कल्पना में होती है। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि यदि वास्तविक जीवन में खुशियां नहीं हैं, तो मन की दुनिया में उन्हें बनाया जा सकता है।

उनकी मां खिड़की के पास बैठकर राह चलते लोगों को देखा करती थीं। वे उनके हावभाव, उनकी चाल और उनके व्यवहार को देखकर कहानियां बनाती थीं। वे उन लोगों की नकल करती थीं और अपने बच्चों को हंसाती थीं। यह केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि जीवन को समझने और महसूस करने का एक माध्यम था। यही वह प्रक्रिया थी, जिसने चैपलिन के भीतर कलाकार को जन्म दिया। उन्होंने सीखा कि जीवन की हर परिस्थिति एक कहानी बन सकती है, यदि उसे देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक हो।

कल्पना की यह शक्ति उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब उनके पास धन नहीं था, तब भी उनके पास सपने थे। जब उनके पास संसाधन नहीं थे, तब भी उनके पास विश्वास था। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन की वास्तविक गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी होती है। यदि मन समृद्ध है, तो जीवन कभी गरीब नहीं होता। यही कारण था कि उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने भविष्य का निर्धारण नहीं करने दिया।

संघर्ष उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया था। वे अखबार बेचते थे और छोटे-मोटे कार्य करके अपने परिवार की सहायता करते थे। यह जीवन आसान नहीं था, लेकिन इसने उन्हें मजबूत बना दिया। उन्होंने कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखा। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए साहस आवश्यक है। डर हमें कमजोर बनाता है, जबकि साहस हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस केवल बड़े कार्य करने में नहीं, बल्कि कठिन समय में हार न मानने में होता है। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, तब हमारा साहस ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। यदि हम अपने भीतर विश्वास बनाए रखते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। चैपलिन ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपने दुखों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। जीवन में दृष्टिकोण का महत्व भी अत्यंत गहरा होता है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन उनका अनुभव अलग-अलग होता है। एक व्यक्ति कठिनाई में निराश हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कठिनाई में अवसर खोज लेता है। यह अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। चैपलिन ने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने संघर्ष को अपने सपनों की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उनका यह विश्वास कि जीवन सुंदर हो सकता है, यदि हम उससे डरें नहीं, हमें एक गहरी शिक्षा देता है। भय हमें सीमित करता है, जबकि साहस हमें मुक्त करता है। जब हम डरते हैं, तो हम अपने सपनों को त्याग देते हैं। लेकिन जब हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। साहस हमें यह विश्वास देता है कि हम अपनी परिस्थितियों से बड़े हैं। जीवन का एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न तो कठिनाइयां हमेशा रहती हैं और न ही दुख हमेशा रहता है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। चैपलिन ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने अपने संघर्ष को अस्थायी माना और अपने सपनों को स्थायी रखा।

उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महानता अचानक नहीं मिलती। यह निरंतर प्रयास, धैर्य और विश्वास का परिणाम होती है। उन्होंने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही विश्वास उन्हें महान बना गया।

आज के समय में, जब लोग छोटी-छोटी समस्याओं से निराश हो जाते हैं, उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपनी कल्पना को जीवित रखते हैं, तो हम हर कठिनाई में अवसर खोज सकते हैं। जब हम साहस बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।

जीवन की वास्तविक सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति में होती है। यदि हमारे पास आत्मविश्वास है, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। यदि हमारे पास कल्पना है, तो हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। यदि हमारे पास साहस है, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

अंततः, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हमारे भीतर विश्वास और साहस है, तो हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जीवन हमें हमेशा अवसर देता है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने की होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वही अपने जीवन को असाधारण बना सकता है। यही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ा सत्य है।

सोशल मीडिया के मोहपाश से मुक्ति की जरूरत

ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में हमारी बढ़ती सक्रियता में सब कुछ ठीक नहीं है -खासकर, जिस प्रकार फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के प्रति आकर्षण हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है: उनके बड़े होने की प्रक्रिया, सामाजिक मेलजोल, शिक्षा और आभासी दुनिया से जुड़ने के उनके ढंग पर। क्या यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, और कई यूरोपीय देश भी इसी राह पर हैं? भारत में भी, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार जोर पकड़ने लगा है। जरा कल्पना करें कि आपके बच्चे पर क्या गुजरेगी जब आप उससे कहें कि कुछ दिन के लिए वह स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करे, और इसकी बजाय ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई करने या अपने दोस्तों व प्रियजनों के साथ सीधे, आमने-सामने बात करें।

जब मैं 16, 14 और 12 वर्षीय उन तीन बहनों के भाग्य के बारे में सोचता हूं, जिन्होंने गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में अपने अपार्टमेंट की नौवीं मंज़िल से कूदकर जान दे दी, तो मुझे सच में डर लगता है। खबरों के मुताबिक, परिवार में कलह रहती थी, और सबसे विशेष बात, पिता अपनी तीनों बेटियों की सोशल मीडिया और टास्क-बेस्ड ऑनलाइन कोरियन गेम्स की लत से खुश नहीं थे। ऐसा लगता है कि वे तीनों यह ‘झटका’ बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला किया। इन दिनों मेरा यह भरोसा पुख्ता होता जा रहा है कि तकनीक दुधारी तलवार है। मसलन, स्मार्टफोन जैसे उपकरण के बारे में सोचिए। यह जादुई है। यह किसी बच्चे या किशोरवय को दें। वह तुरंत पूरी दुनिया से जुड़ जाता है, फिल्म देखेगा, गाने सुनेगा, वीडियो गेम खेलेगा, किताब पढ़ेगा, रील और वीडियो बनाएगा, मैसेज भेजेगा और अपने ढंग से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेगा। यह तकनीकज़दा ‘स्मार्टनेस’ उन्हें प्रभावित करेगी, लेकिन सच तो यह है कि स्मार्टफोन की यह लत उनसे कुछ ज़रूरी चीज़ भी छीन लेती है। जितना ज्यादा वे स्क्रीन की लत में फंसते जाएंगे उतना ही असल दुनिया से दूर होते जाएंगे; जितना ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलेंगे, उतने ही अकेले पड़ते जाएंगे, क्योंकि खुली जगह में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल या क्रिकेट खेलने से परहेज करने लगते हैं; वे जितना ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे, उतना ही ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती चली जाएगी;और सबसे बढ़कर, अपने वीडियो ‘वायरल’ करने में वे जितना ज़्यादा समय खपाते हैं, उनके पास किताब को छूने, पढ़ने, महसूस करने, विश्लेषण करने और अनुभव करने के लिए उतना ही कम समय बचता है।

यही विरोधाभास बताता है कि सोशल मीडिया उपयोग ने बच्चों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है, उनकी व्यग्रता बढ़ा दी है, अवसाद पैदा कर दिया और उनके आत्म-सम्मान को चोट पहुंचाई है। अमेरिकी सामाजिक ज्ञानमनोवैज्ञानिक जोनाथन हैड्ट ने सोचने पर मजबूर कर देने वाली अपनी किताब ‘द एंक्सियस जेनरेशन’ में इस त्रासदी का विश्लेषण किया है। जैसा कि हैड्ट का तर्क है कि डिजिटल युग में पैरेंट्स द्वारा बच्चों पर ध्यान कम दिए जाने की वजह से, लत के समान और परस्पर होड़ करवाने वाले सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच बिना किसी रोक-टोक हो गई है। वहीं, इसी प्रकार, ‘असल दुनिया में ओवर-पैरेंटिंग’ की प्रवृत्ति (हर वक्त बच्चे के पीछे पड़े रहना) हमारे बच्चों की सामान्य विकास प्रक्रिया रोक रही है। यह देखकर दुख होता है कि बचपन अब ‘खेल आधारित’ नहीं रहा; ‘फ़ोन आधारित’ बन गया है। इसलिए, कोई हैरानी नहीं कि स्मार्टफ़ोन हमारे बच्चों को उनके ठीक इर्द-गिर्द के माहौल से दूर करता जा रहा है और असल ज़िंदगी की दोस्ती की जगह सतही ऑनलाइन चैट ले रही है। इसी को लेकर हैड्ट चेताते हैं कि इस ‘व्यग्र पीढ़ी’ में नींद की कमी, ध्यान भटकना और अकेलापन न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। भारत में इस संकट की गंभीरता को समझें — शिक्षा के स्तर की वार्षिक रिपोर्ट (2024) के अनुसार, हमारे 76 प्रतिशत बच्चे (14-16 साल समूह) सोशल मीडिया तक पहुंच करने के लिए स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही भयावह है जोखिमज़दा कच्चे दिमागों पर कंटेंट क्रिएटर्स या यू-ट्यूब ‘इन्फ्लुएंसर’ का प्रभाव। एक स्थिति की कल्पना करें: आपका बच्चा तब तक सो नहीं पाता जब तक वह हर रात किसी मशहूर ‘इन्फ्लुएंसर’ की मनगढ़ंत कहानियां न सुन ले — उत्तराखंड के एक छोटे से शहर का एक नौजवान जिसके 31 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वह अपनी फैंसी कारों— मर्सिडीज-बेंज जी-वैगन, पोर्शे 718 बॉक्सटर और टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर -का गर्वपूर्ण प्रदर्शन करता रहता है! देखने वाले युवा को इस चकाचौंध भरी जीवनशैली से अपनी नाकाबिलियत और आत्म-सम्मान की कमी महसूस हो सकती है। जब इस किस्म का कोई ‘इन्फ्लुएंसर’ कच्चे मन वाले किसी किशोरवय की उम्मीदों को आकार देना शुरू देता है, तो वह यह मानने लग सकता है कि अगर कोई हर सुबह अपने परिवार के क्रिया-कलाप सोशल मीडिया पर डालकर इतना कमा सकता है, तो कड़ी मेहनत करने, मन लगाकर पढ़ाई करने और रचनात्मक कौशल बेहतर बनाने का क्या मतलब। क्या यही वजह है कि हम जहां-तहां युवाओं को फोन से रील बनाते, अपने वीडियो अपलोड करते, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते और त्वरित लोकप्रियता एवं सफलता पाने की कोशिश करते देखते हैं? ‘लाइक और सब्सक्राइब’ — मानो यह हमारे जमाने का पसंदीदा मंत्र बन गया है!

सवाल है हम अपने बच्चों को इस मोहपाश से कैसे बचा सकते हैं। भले ही हम अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के विचार पर एतराज़ करें, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब समय है कि हम कुछ ठोस उपाय करें ताकि यह लत न्यूनतम हो पाए।

अभियान

शिव और शक्ति की दिव्य परंपरा: संतुलित, जागरूक और प्रेमपूर्ण परवरिश का सनातन मार्ग

मानव जीवन में माता-पिता की भूमिका केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे अपने बच्चों के व्यक्तित्व, संस्कार और भविष्य के निर्माता भी होते हैं। एक बच्चा केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि अपने घर के वातावरण, माता-पिता के व्यवहार और उनके द्वारा दिए गए मूल्यों से एक संपूर्ण मनुष्य बनता है। आज के आधुनिक युग में, जहाँ पेरेंटिंग एक जटिल विषय बन चुकी है और हर ओर से अलग-अलग सलाह मिलती है, वहीं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें एक अत्यंत संतुलित और गहरा मार्ग दिखाती है। इस संदर्भ में भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका पारिवारिक जीवन केवल दिव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवंत शिक्षा भी है, जो हर माता-पिता को अपने बच्चों की सही परवरिश का मार्ग दिखाती है।

शिव और शक्ति का संबंध केवल पति-पत्नी का संबंध नहीं है, बल्कि यह संतुलन, प्रेम, सम्मान और समझ का प्रतीक है। यही संतुलन उनकी संतान भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की परवरिश में भी दिखाई देता है। दोनों पुत्र एक ही माता-पिता की संतान होते हुए भी स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन के मार्ग में एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। गणेश जी धैर्य, बुद्धि, विनम्रता और स्थिरता के प्रतीक हैं, जबकि कार्तिकेय जी साहस, ऊर्जा, नेतृत्व और कर्मशीलता के प्रतीक हैं। यह अंतर इस बात का प्रमाण है कि शिव और पार्वती ने अपने बच्चों को एक समान साँचे में ढालने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी व्यक्तिगत प्रकृति को समझकर उन्हें विकसित होने की स्वतंत्रता दी।

आज के समय में माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा भी उसी तरह पढ़े, उसी तरह व्यवहार करे या उसी तरह सफलता प्राप्त करे, जैसा किसी और का बच्चा कर रहा है। लेकिन यह दृष्टिकोण बच्चे के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। शिव और पार्वती का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय होता है। उसकी अपनी क्षमताएँ, रुचियाँ और जीवन का अपना उद्देश्य होता है। माता-पिता का कार्य उसे बदलना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक क्षमता को पहचानना और उसे सही दिशा देना होता है।

शिव और पार्वती का पारिवारिक जीवन इस बात का भी उदाहरण है कि माता-पिता के बीच आपसी सम्मान और एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। शिव का स्वभाव शांत, वैरागी और ध्यानमग्न है, जबकि पार्वती का स्वभाव ममतामयी, संवेदनशील और गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ है। उनके स्वभाव में यह भिन्नता होने के बावजूद, दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। यह संतुलन बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करता है। जब बच्चे अपने माता-पिता को एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग करते हुए देखते हैं, तो उनके भीतर भी वही संस्कार विकसित होते हैं।

परवरिश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—प्रेम और अनुशासन का संतुलन। शिव का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और भोला है, लेकिन वे आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी हो सकते हैं। गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध और कठोरता के बाद भी प्रेम और करुणा का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करके उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया। यह घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि माता-पिता को अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का साहस भी रखना चाहिए। बच्चों को डराकर नहीं, बल्कि प्रेम और समझ के माध्यम से मार्गदर्शन देना ही सच्ची परवरिश है। बच्चों को स्वतंत्रता देना भी परवरिश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। शिव और पार्वती ने अपने बच्चों को उनके जीवन का मार्ग स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दी। कार्तिकेय जी ने अपना मार्ग स्वयं चुना और देवताओं के सेनापति बने, जबकि गणेश जी ने ज्ञान और बुद्धि के मार्ग को अपनाया। माता-पिता ने दोनों के निर्णयों का सम्मान किया और उनका समर्थन किया। यह हमें सिखाता है कि बच्चों को केवल सुरक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का अवसर भी देना चाहिए। आज के समय में कई माता-पिता अपने बच्चों को असफलता से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में असफलता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण शिक्षक होती है। जब बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो वे अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। शिव और पार्वती का दृष्टिकोण यही था कि बच्चों को जीवन के अनुभवों से सीखने दिया जाए, ताकि वे अपने जीवन का सही मार्ग स्वयं खोज सकें।

शिव और शक्ति का जीवन यह भी सिखाता है कि परवरिश केवल भौतिक सुविधाएँ प्रदान करने तक सीमित नहीं है। सच्ची परवरिश वह है, जिसमें बच्चों को प्रेम, सम्मान, नैतिकता और आत्मविश्वास का उपहार दिया जाए। जब बच्चे अपने माता-पिता से यह अनुभव करते हैं कि वे बिना किसी शर्त के उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास विकसित होता है। यह आत्मविश्वास ही उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। परवरिश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है—उपस्थिति। शिव भले ही योगी हैं और ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन वे अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। पार्वती भी अपनी मातृ भूमिका को पूरी संवेदनशीलता और प्रेम के साथ निभाती हैं। यह हमें सिखाता है कि बच्चों के जीवन में माता-पिता की उपस्थिति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी होनी चाहिए।

आज के व्यस्त जीवन में माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते, लेकिन बच्चों के लिए माता-पिता का समय और ध्यान सबसे मूल्यवान होता है। जब माता-पिता अपने बच्चों के साथ संवाद करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो बच्चों के भीतर एक सकारात्मक और संतुलित व्यक्तित्व विकसित होता है।

शिव और शक्ति का जीवन संतुलन का जीवन है। यह संतुलन प्रेम और अनुशासन के बीच, स्वतंत्रता और मार्गदर्शन के बीच, और शक्ति और करुणा के बीच है। यही संतुलन परवरिश का मूल सिद्धांत है। माता-पिता को अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शक बनना चाहिए, लेकिन उनके जीवन पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को दिशा देनी चाहिए, लेकिन उनके सपनों को सीमित नहीं करना चाहिए।

अंततः, शिव और शक्ति की परवरिश की यह दिव्य परंपरा हमें यह सिखाती है कि सच्ची पेरेंटिंग केवल नियमों और नियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समझ, धैर्य और विश्वास का एक सुंदर समन्वय है। जब माता-पिता अपने बच्चों को प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ मार्गदर्शन देते हैं, तो वे केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संतुलित और जागरूक मनुष्य का निर्माण करते हैं। यही सच्ची परवरिश है, और यही वह मार्ग है, जो बच्चों को न केवल जीवन में सफलता दिलाता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर भी ले जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात के गांधीनगर से 'डिजिटल खाद्य वितरण' के एक नए युग की शुरुआत

- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश की सर्वप्रथम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 'डिजिटल इंडिया' का विस्तार आज सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तक पहुंच गया है : केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह
- प्रधानमंत्री के 'सेवा ही साधना' मंत्र और टेक्नोलॉजी के समन्वय से 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' का संकल्प साकार होगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- रियायती अनाज वितरण में सीबीडीसी आधारित व्यवस्था साबरमती नदी के किनारे गरीबी के खिलाफ 'डिजिटल सत्याग्रह' साबित होगी : केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी
- गुजरात में ग्रेन एटीएम और सीबीडीसी मॉडल से नागरिकों को राशन की लाइनों से मुक्ति मिलेगी और अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका पूरा हक मिलेगा : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

- सीबीडीसी जैसी टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था से भ्रष्टाचार और बिचौलियों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा
- यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगले तीन-चार वर्षों में देश भर में लागू होगी
- डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में भारत दुनिया में अग्रणी, दुनिया में हो रहे कुल डिजिटल लेनदेन में भारत की हिस्सेदारी आधे से अधिक
- 'अन्नपूर्ति मशीन' केवल 35 सेकेंड में 25 किलो अनाज का वितरण करेगी, जो वजन, मूल्य और गुणवत्ता की दृष्टि से पूरी तरह सटीक होगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रविवार को गांधीनगर से देश की सबसे पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित पारदर्शी, आधुनिक और सरल सार्वजनिक वितवरण व्यवस्था (पीडीएस) का शुभारंभ किया।

महात्मा मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। इस समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 किलो के सीलबंद पैक में चना और अरहर दाल के वितरण, अहमदाबाद के साबरमती जोन में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम सुविधा और 'गरिमा पोषण-सुपोषित गरुड़ेश्वर तालुका' अभियान का शुभारंभ किया। इसके अलावा, गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (सीईआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू से शिकायतों के निपटारे के लिए प्री-लिटिगेशन इकोसिस्टम विकसित होगा, जिससे अदालतों के बाहर ही विवादों का निपटारा हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, 'उपभोक्ता उत्तरदायित्व सूचकांक' (सीआरआई) तैयार करने के लिए भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 'केयर रेटिंग' और उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से आज 'डिजिटल इंडिया' का विस्तार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तक पहुंच गया है। एक दशक पहले देश के 60 करोड़ लोगों के परिवार में एक भी बैंक खाता नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल लेनदेन में से आधे भारत में हो रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि अब गरीबों को रियायती अनाज देने की दिशा में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन साकार हो रहा है। जिसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) प्रोजेक्ट और 'मेड इन गुजरात' जैसी टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इससे सुदूरवर्ती गांवों, आकांक्षी जिलों और पिछड़े इलाकों में रहने वाले नागरिकों को उनके अधिकार का पूरा अनाज सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीडीसी प्रोजेक्ट में शामिल सभी संस्थानों और केंद्र एवं राज्य के विभागों को बधाई देते हुए कहा कि यह आधुनिक व्यवस्था प्रधानमंत्री के मंत्र 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' को सही मायने में चरितार्थ करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज देश के 81 करोड़ लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्हें मिलने वाली खाद्य सुरक्षा अब डिजिटल और पारदर्शी बन गई है।

आज प्रारंभ किए गए ग्रेन एटीएम, अन्नपूर्ति मशीन और दाल की नई पैकिंग तथा गरिमा पोषण सहित जैसे प्रोजेक्ट का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने इन्हें गरीबों को अन्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न क्रांतिकारी पहलें करार दिया।

श्री शाह ने कहा कि अन्नपूर्ति मशीन से केवल 35 सेकेंड में 25 किलो अनाज का वितरण संभव हो पाएगा, जो वजन, मूल्य और गुणवत्ता की दृष्टि से पूरी तरह से सटीक होगा। आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली, सीबीडीसी और रिजर्व बैंक के पेमेंट सिस्टम से जुड़ी यह व्यवस्था अगले तीन-चार वर्षों में पूरे देश में लागू की जाएगी, जिससे देश भर के गरीबों को उनके अधिकार का गुणवत्तापूर्ण राशन तय समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ मिलेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से गरीब और अंतिम छोर के नागरिकों का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घरों का निर्माण, 13 करोड़ घरों में नल से जल कनेक्शन, लगभग 13 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर और 12 करोड़ घरों में शौचालय की उपलब्धता के साथ ही 2.91 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, जो सरकार की योजनाओं और अभियानों की सफलता को दर्शाता है। इसके अलावा, उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी सफलता के आंकड़े बताए। उन्होंने कहा कि लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में ये योजनाएं महत्वपूर्ण साबित हुई हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़तापूर्वक कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। पिछले एक दशक में किसानों से समर्थन मूल्य अनाज की खरीदी में 15 गुना वृद्धि हुई है और कृषि बजट भी 26,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत के डेयरी, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र को संपूर्ण सुरक्षा कवच दिया गया है, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए दुनिया के बाजार खुल जाएंगे।

अंत में केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीडीसी और पारदर्शी वितरण व्यवस्था के पायलट प्रोजेक्ट के लिए गुजरात का चयन करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और गुजरात सरकार को बधाई दी और इस लीक-प्रूफ सिस्टम को विकसित भारत का ब्लू प्रिंट करार दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 'जो कहना, वह करना' के मंत्र के साथ देश में जनकल्याण का एक नया इतिहास रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 'ज्ञान' अर्थात गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के सशक्तिकरण के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी है।

मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी के परिवर्तनकारी प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब भारत में डिजिटल भुगतान को लेकर लोगों के मन में शक-संदेह था, उन शंकाओं को दूर कर आज भारत दुनिया में सबसे बड़े यूपीआई यूजर के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिवेणी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डेटाबेस कनेक्टिविटी के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे और विश्वसनीयता के साथ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। आहार, आवास, आरोग्य और आय के स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप पिछले एक दशक में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब अनाज प्राप्त करने के लिए 'ग्रेन एटीएम' कार्यरत होंगे। इस एटीएम से केवल 35 सेकेंड में 25 किलो अनाज का वितरण संभव होगा और ये 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। इस सुविधा के कारण विशेष रुप से श्रमिक और मजदूर वर्ग अपने कार्य समय के घंटों के बाद भी किसी भी समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने योग्य गेहूं, चावल और दाल प्राप्त कर सकते हैं, जो हाशिए पर खड़े लोगों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।

सीबीडीसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभार्थियों को डिजिटल टोकन के द्वारा सब्सिडी, वस्तु का वजन और उसकी कीमत की सटीक जानकारी मिलेगी। इस डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के कारण योजना के लाभों में 100 फीसदी पारदर्शिता आएगी और 'सेचुरेशन एप्रोच' यानी प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचने का सरकार का संकल्प सही मायने में साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि हाल ही में अमूल एआई द्वारा पशुपालकों को एआई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के बाद अब सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का यह प्रयोग एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के मंत्र 'सेवा ही साधना' का अनुसरण करते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाकर वर्ष 2047 तक 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीबीडीसी आधारित यह केवल टेक्नोलॉजी ऐप और पोर्टल ही नहीं है, बल्कि इससे सभी जरूरतमंदों लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनके अनाज प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े खाद्य कार्यक्रम को इस नई पहल से विशेष बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनाज वितरण व्यवस्था को इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना एक चुनौती थी, लेकिन 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत यह कार्य बहुत आसान बन गया।

केंद्रीय मंत्री श्री जोशी ने कहा कि देश भर में राशन कार्ड का डिजिटलीकरण होने से 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की संकल्पना साकार हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पहल से शुरू हुई डिजिटल कूपन के जरिए लाभार्थी किसी भी समय ग्रेन एटीएम पर जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके अनाज प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, साधारण फीचर फोन उपयोगकर्ता लाभार्थी को भी एसएमएस के जरिए प्राप्त ओटीपी से अनाज की सुविधा दी जाएगी।

श्री जोशी ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के लागू होने से लगभग दो से तीन करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द हो चुके हैं। सीबीडीसी आधारित व्यवस्था शुरू होने से वास्तविक लाभार्थी को ही उसका लाभ मिलेगा। इस अनाज की डिजिटल रकम लाभार्थी के वॉलेट में जमा होने से वह इसके जरिए उचित मूल्य की दुकान और ग्रेन एटीएम से अनाज की खरीदी कर सकेगा, जबकि अन्य स्थानों पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस डिजिटल आधारित अनाज वितरण प्रक्रिया की गुजरात से शुरुआत होने से देश के बाकी राज्यों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जाली राशन कार्ड भी अपने तरीके से समाप्त हो जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रियायती अनाज वितरण में सीबीडीसी आधारित व्यवस्था साबरमती नदी के किनारे गरीबी के खिलाफ 'डिजिटल सत्याग्रह' साबित होगी, जिससे कालाबाजारी पर भी और रोक लगेगी और जरूरतमंद लाभार्थी तक अनाज तेजी से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग को आगामी समय में देश भर में लागू किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि देश की डिजिटल करेंसी गरीब की थाली तक अनाज पहुंचाएगी। आज गुजरात की धरती पर एक बार फिर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। हम सभी हम सभी लोग एक ऐसी क्रांति के गवाह बनने जा रहे हैं, जो केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की दिशा और दशा बदल देगी।

श्री संघवी ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में 'खाद्य सुरक्षा' हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। अतीत में सरकारी अनाज लाभार्थी तक पहुंचने से पहले बिचौलियों तक पहुंच जाता था और राशन की दुकानों पर लंबी कतारों जैसे समस्याएं देखने को मिलती थीं। सीबीडीसी आधारित पीडीएस प्रोजेक्ट इन सभी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करेगा।

उन्होंने कहा कि आम तौर पर नई टेक्नोलॉजी का पहला लाभ बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने एक राह दिखाई है। 'डिजिटल करेंसी' जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का सबसे पहला उपयोग गरीब की थाली तक भोजन पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अब, लाभार्थियों को दुकानदारों की राह देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चौबीसों घंटे, किसी भी वक्त ग्रेन एटीएम पर जाकर केवल 5 मिनट में ही अनाज प्राप्त किया जा सकता है। इस व्यवस्था में वजन में 1 ग्राम का भी अंतर नहीं होगा, जो डिजिटल इंडिया का उत्तम उदाहरण है। सीबीडीसी, ग्रेन एटीएम और बायोमेट्रिक जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा गुजरात का यह मॉडल आगामी समय में देश के लिए पथप्रदर्शक बनेगा और पात्र लोगों को उनका अधिकार पारदर्शी तरीके से और बिना किसी परेशानी के मिलेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री मोना खंधार ने स्वागत भाषण में पूरे कार्यक्रम और नए प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई-रूपी की घोषणा के साथ देश में आधुनिक फिनटेक के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व करने के लिए गुजरात तैयार है।

कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन बांभणिया, गुजरात के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी, राज्य मंत्री श्री पी.सी. बरंडा, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, कई सांसद और विधायक, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री पी. वासुदेव, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री डी. सुरेन्द्रन और केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

शेयर बाजार की तेज गिरावट से दिग्गज कंपनियों की साख पर चोट, आईटी और बैंकिंग सेक्टर को भारी नुकसान

(जीएनएस)। देश के शेयर बाजार में पिछले सप्ताह आई तेज गिरावट ने भारतीय कॉरपोरेट जगत की बड़ी कंपनियों को गहरा झटका दिया है। बाजार के कमजोर रुख के कारण देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से छह कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट का असर विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, टेलीकॉम और बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों पर देखने को मिला, जिससे निवेशकों की संपत्ति में भी बड़ी कमी आई और बाजार की धारणा नकारात्मक हो गई। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में लगातार दबाव बना रहा और प्रमुख सूचकांकों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों की सतर्कता, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत और चुनिंदा शेयरों में मुनाफावसूली के कारण बाजार का रुख कमजोर रहा। प्रमुख सूचकांक में करीब 953 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया और बड़े शेयरों में बिकवाली को बढ़ावा दिया। इसका सीधा असर देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों के बाजार मूल्य पर पड़ा।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को इस गिरावट का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। देश की अग्रणी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services के बाजार पूंजीकरण में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक घटकर करीब 9.7 लाख करोड़ रुपये रह गया। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाओं की मांग में अनिश्चितता और निवेशकों की सतर्कता का असर इस क्षेत्र पर पड़ा है। इसी तरह देश की एक अन्य प्रमुख आईटी कंपनी Infosys के बाजार मूल्य में भी लगभग 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और इसका कुल मूल्यांकन घटकर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपये रह गया। आईटी क्षेत्र का वैश्विक बाजारों से गहरा जुड़ाव होता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव इन कंपनियों के प्रदर्शन और मूल्यांकन पर पड़ता है।

बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी इस गिरावट से अछूती नहीं रहीं। देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC Bank के बाजार पूंजीकरण में लगभग 54 हजार करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि निवेशकों ने वित्तीय क्षेत्र के कुछ शेयरों में मुनाफावसूली की और बाजार की अनिश्चितता के कारण सतर्क रुख अपनाया। इसी तरह देश की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries के बाजार मूल्य में भी लगभग 42 हजार करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है, लेकिन बाजार की कमजोरी का असर इसके मूल्यांकन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

बीमा और टेलीकॉम क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ा। सरकारी बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Life Insurance Corporation of India के बाजार पूंजीकरण में लगभग 24 हजार करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह देश की अग्रणी टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel के बाजार मूल्य में भी करीब 19 हजार करोड़ रुपये की कमी आई। इन कंपनियों के बाजार मूल्य में आई गिरावट से यह स्पष्ट होता है कि बाजार की कमजोरी का असर विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों पर व्यापक रूप से पड़ा है।

हालांकि बाजार में समग्र रूप से गिरावट का माहौल रहा, लेकिन कुछ कंपनियों ने इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी मजबूती दिखाई। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक State Bank of India के बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और इसका कुल मूल्य 11 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि बैंकिंग क्षेत्र के कुछ शेयरों में निवेशकों का विश्वास बना हुआ है और उन्होंने इस गिरावट के दौरान भी इन कंपनियों में निवेश जारी रखा।

इसी तरह वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Bajaj Finance के बाजार मूल्य में भी लगभग 26 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Larsen & Toubro के बाजार पूंजीकरण में भी करीब 14 हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। निजी बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ICICI Bank के शेयरों में भी सीमित लेकिन सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। इन कंपनियों की मजबूती इस बात का संकेत है कि बाजार में गिरावट के बावजूद निवेशकों ने कुछ मजबूत और स्थिर कंपनियों में भरोसा बनाए रखा।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बाजार में मुनाफावसूली के कारण इस तरह की गिरावट देखने को मिली। आईटी क्षेत्र पर विशेष रूप से दबाव इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र की आय का बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों से आता है और वैश्विक मांग में किसी भी तरह की अनिश्चितता का सीधा असर इन कंपनियों पर पड़ता है। वहीं बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के कुछ शेयरों में मजबूती यह दर्शाती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है।

साबरमती स्टेशन पर पुनर्विकास के अंतर्गत हाई रूफ निर्माण हेतु ट्रस (Truss) का सफल लॉन्च यात्री सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम

(जीएनएस)। भारतीय रेल द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं आधुनिक अवसंरचना विकास की दिशा में साबरमती स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इस पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत स्टेशन पर ट्रैकों के ऊपर विशाल हाई-रूफ एवं कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने के साथ-साथ यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। दिनांक 15.02.2026 को मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने स्टेशन पर तीव्र गति से चल रहे पुनर्विकास कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 4/5 एवं 2/3 के ऊपर हाई-रूफ निर्माण के लिए लॉन्च किए गए 28 मीटर लंबे ट्रस का अवलोकन किया।

निर्माणाधीन हाई-रूफ का प्लेटफॉर्म संख्या 4 से 7 के बीच ट्रस लॉन्चिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। जिसका प्लेटफॉर्म संख्या 7 से प्लेटफॉर्म संख्या 1 तक तथा आगमन फुटओवर ब्रिज से सर्कुलेटिंग एरिया तक विस्तार होगा।

कॉन्कोर्स क्षेत्र में विशाल प्रतीक्षालय (वेटिंग हॉल) एवं फूड प्लाजा जैसी आधुनिक सुविधाए भी होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर आराम एवं खानपान की सुविधा प्राप्त होगी। कॉन्कोर्स का क्षेत्रफल लगभग 110×36 वर्गमीटर होगा। वहीं हाई-रूफ का आकार 122×171 मीटर तथा 88×110 मीटर होगा, जिससे कुल लगभग 30,542 वर्गमीटर क्षेत्र ट्रैकों के ऊपर कवर होगा। यह छत प्लेटफॉर्म से लगभग 65 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की जा रही है।

इसी क्रम में 28×4.25×3.25 मीटर आकार एवं लगभग 26 टन वजनी एक विशाल ट्रस को 65 फीट की ऊंचाई पर 810 टन क्षमता वाली क्रेन की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कार्यस्थल की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद यह कार्य 8 घंटे के मेगा ब्लॉक के दौरान सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत यात्रियों की सुगमता हेतु 20 लिफ्ट, 20 एस्केलेटर तथा 20 सीढ़ियों का प्रावधान किया जा रहा है। इन आधुनिक सुविधाओं से यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी तथा स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर स्वयंभू भवनाथ महादेव की श्रद्धाभाव से पूजा-अर्चना की

- मुख्यमंत्री ने आस्था के महाकुंभ महाशिवरात्रि के मेले में शामिल होकर धन्यता महसूस की
- मुख्यमंत्री ने भवनाथ मंदिर परिसर में गिरनार तीर्थक्षेत्र और अलग-अलग अखाड़ों के साधु-संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर संतों का सम्मान और अभिवादन किया
- ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया भी भवनाथ महादेव के दर्शन-पूजन में श्रद्धाभाव से शामिल हुए मुख्यमंत्री ने भवनाथ मंदिर परिसर में भक्तों के साथ सहजता से बातचीत कर उनका अभिवादन किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गिरनार पर्वत की गोद और भवनाथ तलहटी में बिराजमान स्वयंभू भवनाथ महादेव के श्रद्धाभाव के साथ दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया भी श्रद्धापूर्वक भवनाथ महादेव के दर्शन और पूजा में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जूनागढ़ में परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले पांच दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के अंतिम दिन भवनाथ मंदिर परिसर में साधु-संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें अंगवस्त्र अर्पित किया और विशेष सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया।

संत समागम के लिए प्रसिद्ध इस महाशिवरात्रि के मेले में मुख्मयंत्री ने साधु-संतों के साथ मुलाकात कर आध्यात्मिक चेतना की भी अनुभूति की।

श्री भूपेंद्र पटेल ने भवनाथ मंदिर में स्थित अखंड धूणा (धूनी) के भी दर्शन किए और बाद में मृगी कुंड में श्रद्धापूर्वक नमन किया।

मुख्यमंत्री ने आस्था के महाकुंभ महाशिवरात्रि के मेले में भवनाथ मंदिर परिसर के सत्संग हॉल में श्री मुक्तानंद बापू, श्री शेरनाथ बापू, श्री हरिहरानंद बापू, श्री महेश गिरि बापू, श्री महेन्द्रानंद गिरि बापू, श्री संपूर्णानंदजी बापू, श्री राजेन्द्रदास बापू, श्री भारद्वाज गिरि बापू, श्री बुद्ध गिरि बापू, श्री सोमनाथ जी बापू सहित अन्य साधु-संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही, उन्होंने साधु-संतों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर अभिवादन किया। इस अवसर पर जिले के पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहे।

इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री अनिल कुमार राणावसिया और गुजरात पवित्र यात्राधाम बोर्ड के सदस्य सचिव श्री रमेश मेरजा ने स्मृति चिह्न भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत-सम्मान किया। इसके साथ ही ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया का भी स्मृति चिह्न भेंट कर प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया।

प्रांत और मेला अधिकारी श्री चरणसिंह गोहिल ने महाशिवरात्रि के मेले के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने भवनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ सहजतापूर्वक बातचीत की और उनका अभिवादन किया।

उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि के मेले में अलग-अलग अखाड़ों के साधु-संतों और दिगंबर साधुओं की महाशिवरात्रि पर्व पर निकलने वाली रवेड़ी (शाही सवारी) का भी विशेष महत्व है।

भवनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री का महापौर श्री धर्मेशभाई पोशिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हरेशभाई ठुम्मर, सांसद श्री राजेशभाई चुड़ासमा, विधायक श्री संजयभाई कोरड़िया, श्री देवाभाई मालम, श्री भगवानजीभाई करगटिया, उप महापौर श्री आकाशभाई कटारा, मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष सुश्री पल्लवीबेन ठाकर, शासक पक्ष के नेता श्री मननभाई अभाणी, दंडक श्री कल्पेशभाई अजवाणी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री चंदुभाई मकवाणा, शहर भाजपा अध्यक्ष श्री गौरवभाई रूपारेलिया, अग्रणी श्री धवलभाई दवे, श्री पुनितभाई शर्मा, सावज डेयरी के चेयरमैन श्री दिनेशभाई खटारिया, अग्रणी श्री वेलजीभाई मसाणी सहित कई पदाधिकारी और अधिकारियों ने स्वागत किया।

पश्चिम रेलवे

कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट

सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (कोचिंग) मुंबई सेंट्रल-08 टेंडर नोटिस नंबर WR-MMCT0ECOA (ECTD)/21/2024 O/o SRDEE/CHG/MMCT/W (कंप्यूटर नंबर 545238) तारीख: 11/02/2026 आमंत्रित करता है। काम का नाम: रेलवे SGAC कोच में लगे 25 KVA इन्वर्टर बनाने वाली मेसर्स ऑटोमीटर के लिए तीन साल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। काम की लगभग कीमत: ₹3,25,09,080/- बिड सिक्योरिटी: ₹3,12,600/- जमा करने की तारीख और समय: दि. 10.03.2026 को 15.00 बजे तक। खुलने की तारीख और समय: दि. 10.03.2026 को 15.30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1119

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

विविध कार्य

उप मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (निर्माण), द्वितीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, डीआरएम कार्यालय, प्रतापनगर, पश्चिम रेलवे, वडोदरा-390004 निविदा सूचना संख्या S&T/C/BRC/141/2025-26, दिनांक: 11.02.2026 आमंत्रित करता है। काम का नाम और जगह: "Dy. CSTE कंस्ट्रक्शन, वडोदरा, गुजरात (पश्चिम रेलवे) के तहत WTPS साइडिंग के लिए सेवलिया स्टेशन पर ट्रैक सर्किट वर्क के कनेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (Hitachi Make) सिस्टम और आउटडोर सिग्नलिंग सिस्टम द्वारा हॉट स्टैंड का डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, बदलाव, टेस्टिंग और कमीशनिंग"। काम की अनुमानित लागत: ₹ 3,86,77,172.84 EMD: ₹3,43,400.00 ई-टेंडर जमा करने की तारीख और समय: 09.03.2026 को 15.00 बजे तक। ई-टेंडर खोलने की तारीख और समय: दि. 09.03.2026 को 15.30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1116

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

वाणिज्य शाखा -ई-नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रतलाम मंडल-पश्चिम रेलवे ने पार्सल स्पेस की लीज के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को IREPS वेबसाइट (ई-ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। केटलॉग सं. लीजिंग आर टी एम Leasing-1182601, अनुबंध का प्रकार - Leasing of SLR Compartment, लॉट नं Train No. 11125-SLR-F1-RTM-GWL, 19303-SLR-F1-INDB-BPL, 21125-SLR-F1-RTM-BIX, 19343-SLR-F1-INDB-NIR, 19343-SLR-F2-INDB-NIR, 19343-SLR-R1-INDB-NIR, 59387-SLR-R1-NAD-INDB, 11125-SLR-R1-RTM-GWL, 14802-SLR-F1-INDB-JU, 19303-SLR-R1-INDB-BPL, 21125-SLR-R1-RTM-BIX, 14802-SLR-RI-INDB-JU, 19303-SLR-F2-INDB-BPL, 59387-SLR-F1-NAD-INDB. अनुबंध की अवधि- 03 YEARS, ई- नीलामी की तिथि और समय सभी लॉट के लिए ई-नीलामी दि.02.03.2026 को 10:00 बजे प्रारंभ होगी प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंध करने का अंतराल 10 मिनट है। IREPS के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

V/457 वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रतलाम मंडल-पश्चिम रेलवे

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें : x.com/WesternRly

डॉक्टरों की आड़ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश, दिल्ली ब्लास्ट ने उजागर किया 'अंसार अंतरिम' का खतरनाक नेटवर्क

(जीएनएस)। देश की राजधानी नई दिल्ली में हुए विस्फोट से जुड़े मामले में जांच एजेंसियों ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने सुरक्षा तंत्र और समाज दोनों को गहराई से झकझोर दिया है। श्रीनगर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की संयुक्त जांच में एक कथित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जिसके कुछ सदस्य पेशे से डॉक्टर बताए जा रहे हैं। इस मॉड्यूल को 'अंसार अंतरिम' नाम दिया गया है और एजेंसियों का दावा है कि इसी नेटवर्क ने राजधानी में स्थित ऐतिहासिक लाल किला के पास हुए बम धमाके की साजिश रची थी। इस खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी संगठन अब अपने नेटवर्क को छिपाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित और विश्वसनीय पेशों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी पहचान करना और भी कठिन हो गया है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकी नेटवर्क की नींव अप्रैल 2022 में श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र में हुई एक कथित गुप्त बैठक के दौरान रखी गई थी। इस बैठक में डॉक्टर मुजमिल गनी, उमर-उन-नबी और अदील राथर जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने मिलकर एक संगठित मॉड्यूल बनाने का निर्णय लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार अदील राथर को इस मॉड्यूल का प्रमुख बनाया गया, जबकि मौलवी इरफान को उसका डिप्टी नियुक्त किया गया था। यह नेटवर्क धीरे-धीरे अपने विस्तार की दिशा में काम करता रहा और अपने सदस्यों को संगठित कर एक बड़ी साजिश की तैयारी करता रहा। एजेंसियों का मानना है कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य केवल कश्मीर तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के अन्य प्रमुख शहरों को भी निशाना बनाना था, जिससे व्यापक स्तर पर भय और अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा सके।

जांच में यह भी सामने आया है कि मॉड्यूल के सदस्य तकनीकी रूप से काफी सक्रिय थे और उन्होंने इंटरनेट का उपयोग कर विस्फोटक बनाने से संबंधित जानकारी हासिल की। ऑनलाइन वीडियो, मैनुअल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए वे आईईडी और टीएटीपी जैसे खतरनाक विस्फोटकों के निर्माण की तकनीक सीख रहे थे। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, पर आरोप है कि उसने हरियाणा के फरीदाबाद और नूंह जैसे इलाकों से विस्फोटक सामग्री जुटाई थी। इसके अलावा उसने फरीदाबाद स्थित एक विश्वविद्यालय के पास किराए पर कमरा लिया था, जहां से कथित तौर पर इस नेटवर्क की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। इस कमरे का उपयोग न केवल सामग्री रखने के लिए किया गया, बल्कि वहां विस्फोटक बनाने और साजिश की योजना तैयार करने का भी काम किया गया।

जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क किसी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र या धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहता था, ताकि अधिकतम नुकसान और दहशत फैलाई जा सके। हालांकि, श्रीनगर में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी और विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के बाद मॉड्यूल के सदस्य दबाव में आ गए और उन्होंने अपनी योजना को समय से पहले अंजाम देने का निर्णय लिया। इसी क्रम में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोट किया गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई। यह घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई और इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए व्यापक स्तर पर जांच शुरू की।

इस पूरे मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अक्टूबर 2023 में श्रीनगर के बाहरी इलाकों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पोस्टर पाए गए। इन पोस्टरों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान शुरू की। इसके बाद स्थानीय स्तर पर कुछ गिरफ्तारियां की गईं, जिनसे पूछताछ के दौरान इस मॉड्यूल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। इन सुरागों के आधार पर जांच एजेंसियों ने धीरे-धीरे इस नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कीं और इसके सदस्यों तथा उनके संपर्कों की पहचान की।

इस खुलासे ने यह भी दिखाया है कि आतंकवादी संगठन अब पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीक और पेशेवर पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर जैसे पेशे, जिन्हें समाज में सेवा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, उनका उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना एक गंभीर और चिंताजनक संकेत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आतंकवादी संगठन अपनी पहचान छिपाने और जांच एजेंसियों से बचने के लिए नई-नई रणनीतियां अपना रहे हैं।

जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों, सहयोगियों और फंडिंग स्रोतों की पहचान करने में जुटी हुई हैं। इसके लिए, विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। डिजिटल उपकरणों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क के व्यापक स्वरूप और इसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया जा सके। एजेंसियों का मानना है कि इस मॉड्यूल के कुछ सदस्य अभी भी सक्रिय हो सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यह आवश्यक हो गया है कि सुरक्षा एजेंसियां न केवल पारंपरिक खतरों पर ध्यान दें, बल्कि ऐसे छिपे हुए नेटवर्क की पहचान करने के लिए आधुनिक तकनीक और खुफिया तंत्र को और मजबूत करें। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की आवश्यकता है।

इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। हालांकि, इस खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता और मजबूत खुफिया तंत्र कितना आवश्यक है। यह घटना एक चेतावनी भी है कि आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है और उससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी अपनी रणनीतियों को लगातार विकसित करना होगा, ताकि देश की शांति और सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित किया जा सके।

धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई और बढ़ते ध्रुवीकरण पर मीरवाइज की चिंता, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील

(जीएनएस)। कश्मीर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक नेता मीरवाइज उमर फारूक ने देश में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्रीनगर और बडगाम में आयोजित एक धार्मिक सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के सामने इस समय कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिससे समुदाय के भीतर असुरक्षा और बेचैनी का माहौल बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के समय में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और समुदाय के लोगों के खिलाफ घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने इस स्थिति को लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि ऐसे हालात में समाज के सभी वर्गों को मिलकर शांति और भाईचारे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

मीरवाइज ने कहा कि भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक देश में सभी समुदायों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता या सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है, तो इससे विश्वास का संकट पैदा होता है। उनके अनुसार, यह समय संवाद और समझदारी से समस्याओं को सुलझाने का है, न कि टकराव और विभाजन को बढ़ावा देने का। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण लोकतंत्र की मूल भावना का हिस्सा है और इसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि समुदाय के भीतर बढ़ती चिंता और भय को दूर करने के लिए सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सामाजिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज के कमजोर और बेआवाज लोगों की आवाज बनें और उन्हें न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिलाएं। उनके अनुसार, समाज में शांति और स्थिरता तभी संभव है जब सभी नागरिकों को समान अवसर और सुरक्षा का अनुभव हो। उन्होंने यह भी कहा कि देश की ताकत उसकी विविधता में निहित है और इस विविधता को बनाए रखना राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।

आगामी रमजान महीने को लेकर भी मीरवाइज उमर फारूक ने विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना आत्मचिंतन, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता का समय होता है। इस दौरान लोग प्रार्थना, रोजा और दान के माध्यम से अपने जीवन को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष रमजान के दौरान धार्मिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के संपन्न होंगी और लोगों को अपनी आस्था के अनुसार पूजा-अर्चना करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की नमाज, जुमातुल-विदा, शब-ए-कद्र और ईद जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर लोगों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।

मीरवाइज ने यह भी कहा कि धार्मिक पर्व केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज के लिए आपसी समझ और सहयोग का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी समुदायों से अपील की कि वे एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में सहयोग दें। उनके अनुसार, धार्मिक सहिष्णुता और परस्पर सम्मान ही एक मजबूत और स्थिर समाज की नींव होते हैं।

उन्होंने वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा और संघर्ष के कारण आम लोगों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से फिलिस्तीन और पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के हालात मानवता के लिए चिंताजनक हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उनके अनुसार, वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना केवल राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को इसमें योगदान देना चाहिए।

महाशिवरात्रि से लौटते समय मातम: जेतपुर रेलवे पुल पर दर्दनाक हादसे में तीन युवाओं की मौत

(जीएनएस)। राजकोट। आस्था और उत्सव से भरी एक यात्रा उस समय दर्दनाक त्रासदी में बदल गई जब गुजरात के राजकोट जिले के जेतपुर शहर में रेलवे पुल पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल की संरचना से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में तीन युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। यह हादसा रविवार को जेतलसर जंक्शन रेलवे ब्रिज पर हुआ, जब चार दोस्त जूनागढ़ में आयोजित प्रसिद्ध भावनाथ मेले से लौट रहे थे। यह मेला हर वर्ष जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है और इसमें हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं।

बताया जा रहा है कि चारों युवक मेले में शामिल होकर लौट रहे थे और उनके मन में धार्मिक उत्साह और यात्रा की थकान दोनों मौजूद थे। लेकिन जेतलसर जंक्शन रेलवे पुल पार करते समय अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति काफी तेज थी और जैसे ही चालक ने वाहन को संभालने की कोशिश की, वह संतुलन खो बैठा। अगले ही पल कार सीधे पुल की मजबूत लोहे की संरचना से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार दो हिस्सों में बंट गई और उसके टुकड़े सड़क के अलग-अलग दिशाओं में जा गिरे। यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी।

इस दर्दनाक हादसे में 21 वर्षीय मुस्कान बगड़ा, जो रायडी गांव की निवासी थीं, और 20 वर्षीय अरुण वाला, जो नवागढ़ के रहने वाले थे, की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की जिंदगी एक पल में खत्म हो गई, जिससे उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

वहीं गंभीर रूप से घायल जयदीप चौहान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार यह हादसा तीन परिवारों के लिए हमेशा के लिए अपूरणीय क्षति बन गया। चौथे युवक अमित परमार गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जूनागढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी, राहगीर और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। दुर्घटनास्थल का दृश्य अत्यंत भयावह था। कार के टुकड़े पुल पर बिखरे पड़े थे और चारों युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे। स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत घायलों को बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस और राहत दल ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया और पुल पर यातायात को फिर से सामान्य करने का प्रयास किया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए पुल पर लंबा जाम लग गया था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना इस हादसे का प्रमुख कारण हो सकता है। साथ ही महाशिवरात्रि के अवसर पर क्षेत्र में भारी यातायात भी था, जिससे सड़क पर दबाव बढ़ गया था।

ऊर्जा नीति पर अडिग भारत: अमेरिकी दावों के बीच रूस से तेल खरीद पर राष्ट्रीय हित को दी प्राथमिकता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक कूटनीति और ऊर्जा राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों और आर्थिक स्थिरता पर आधारित है। हाल ही में अमेरिका की ओर से यह दावा किया गया कि भारत ने रूस से अतिरिक्त कच्चा तेल नहीं खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन भारत सरकार ने इन अटकलों को संतुलित और व्यावहारिक तरीके से संबोधित करते हुए यह संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता केवल ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित हैं, न कि किसी बाहरी दबाव के आधार पर लिए गए निर्णय।

यह पूरा मामला उस समय चर्चा में आया जब जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारत के साथ हुई बातचीत में यह संकेत मिला है कि भारत रूस से अतिरिक्त तेल खरीदने के मामले में सावधानी बरत रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर बना दिया है और पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी ऊर्जा आय को सीमित करने की कोशिश की है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के साथ हुए व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए यह दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीद के मामले में सहयोग करेगा। इस घोषणा के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को वापस लेने का निर्णय भी लिया, जिसे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। हालांकि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यह दोहराया कि उसकी ऊर्जा नीति किसी एक देश या राजनीतिक दबाव पर आधारित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह देश की ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में से एक है और उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। उद्योग, परिवहन, बिजली उत्पादन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसे में सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने अपने तेल को रियायती दरों पर एशियाई देशों को उपलब्ध कराया, जिसका लाभ भारत को भी मिला। इससे भारत को कम कीमत पर तेल खरीदने का अवसर मिला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिली।

भारत ने हमेशा यह नीति अपनाई है कि वह अपने ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करेगा, ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों से भी तेल आयात करता है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी एक क्षेत्र में आपूर्ति प्रभावित होती है, तो अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जा सके। यह रणनीति भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की विदेश और ऊर्जा नीति में रणनीतिक स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत न तो किसी वैश्विक शक्ति के दबाव में अपने निर्णय लेना चाहता है और न ही अपनी आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालना चाहता है। भारत का यह दृष्टिकोण उसे वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। भारत अमेरिका के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, लेकिन साथ ही वह रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को भी बनाए रखना चाहता है। रूस लंबे समय से भारत का महत्वपूर्ण रक्षा और ऊर्जा सहयोगी रहा है, और दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैश्विक राजनीति में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुकी है। ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह कूटनीतिक और रणनीतिक शक्ति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ऐसे में भारत जैसे बड़े और उभरते हुए राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने निर्णय पूरी तरह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ले।

भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह भविष्य में भी अपनी ऊर्जा नीति में संतुलन बनाए रखेगी और किसी भी निर्णय से पहले आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करेगी।

SIR प्रक्रिया पर सियासी संग्राम तेज, ओवैसी ने उठाए नागरिकता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल

(जीएनएस)। Asaduddin Owaisi ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए नागरिकता और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई हैं। All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen के अध्यक्ष और सांसद के रूप में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा लागू की जा रही SIR प्रक्रिया केवल एक प्रशासनिक या तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है, जिसका उद्देश्य देश के कुछ वर्गों के अधिकारों को कमजोर करना हो सकता है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र की मूल भावना को प्रभावित कर सकती है और नागरिकों के मताधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से सीमित करने का प्रयास है।

ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं चलता, बल्कि यह सुनिश्चित करने से चलता है कि हर पात्र नागरिक को बिना किसी भय या भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं होगी, तो यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता और मताधिकार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो यह उसके नागरिक होने की स्थिति पर भी प्रश्नचिह्न लगा सकता है।

अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने Bharatiya Janata Party पर आरोप लगाया कि वह SIR प्रक्रिया का उपयोग एक राजनीतिक उपकरण के रूप में कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुधार के लिए नहीं, बल्कि चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले इस प्रक्रिया को Bihar में लागू किया गया और अब इसे Telangana और Maharashtra में लागू करने की तैयारी चल रही है। उनके अनुसार, यह एक सुनियोजित कदम हो सकता है, जिसके जरिए कुछ खास समुदायों और सामाजिक वर्गों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश की जा सकती है।

ओवैसी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हर नागरिक को समान अवसर और समान अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सतर्क रहें और यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाया जाता है, तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

इस मुद्दे पर उन्होंने Election Commission of India की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसे किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर संदेह उत्पन्न होता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है।

ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता केवल एक कानूनी स्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की पहचान और उसके अधिकारों का आधार है। उन्होंने कहा कि यदि नागरिकता से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं होगी, तो इससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, न कि उन्हें कमजोर करे।

इस दौरान उन्होंने हाल ही में आयोजित Medaram Jatara के दौरान हुई एक घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में एक मुस्लिम विक्रेता के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया, जो सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने Telangana Police से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी इस प्रकार की घटनाओं में महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, ताकि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। उन्होंने सरकार और संबंधित एजेंसियों से अपील की कि वे इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं।

ओवैसी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ भी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक और हर संस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, तो यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास है, जो नागरिकों और सरकार के बीच स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि यदि इस विश्वास को कमजोर किया जाता है, तो यह देश की स्थिरता और प्रगति के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं।

इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक ओर सरकार का कहना है कि इस प्रकार की प्रक्रियाएं चुनावी व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए

डायमंड सिटी में संस्कृति का महासंगम: 'नायिका 5.0' और 'रंगिनी' ने रचा इतिहास, सूरत को दिलाई वैश्विक पहचान

(जीएनएस)। गुजरात का औद्योगिक हृदय माने जाने वाला सूरत अब केवल हीरे और टेक्सटाइल का ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और रचनात्मकता का भी चमकता हुआ केंद्र बनता जा रहा है। इस सांस्कृतिक जागरण की एक भव्य मिसाल तब देखने को मिली जब सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ताल ग्रुप और 'रंगिनी' के संयुक्त तत्वावधान में सूरत साइंस सेंटर में 'नायिका 5.0' और 'रंगिनी' फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। इस आयोजन ने न केवल हजारों कलाकारों, विद्यार्थियों और कला प्रेमियों को एक मंच पर जोड़ा, बल्कि लोक कला और लोक नृत्य के अभूतपूर्व संगम के माध्यम से एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर सूरत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव के साथ अंकित कर दिया।

यह आयोजन अपने आप में केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह भारतीय परंपरा, नारी शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा का जीवंत उत्सव बन गया। ताल ग्रुप की फाउंडर डायरेक्टर और प्रसिद्ध कोरियोग्राफर आर्किटेक्ट कृतिका शाह ने इस अवसर पर कहा कि 'नायिका' एक आंदोलन है, जो स्त्रीत्व की गरिमा, शक्ति और सृजनात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन आगामी 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी के रूप में किया गया, ताकि महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और सामाजिक योगदान को एक सशक्त मंच मिल सके। इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन और जागरूकता लाने की एक प्रभावशाली शक्ति भी है।

'रंगिनी' फेस्टिवल के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। इन वर्कशॉप्स का उद्देश्य भारत की प्राचीन और लुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना था। देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री कलाकारों ने इस आयोजन में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया और युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण दिया। पिथौरा आर्ट के प्रसिद्ध विशेषज्ञ परेशभाई राठवा ने बच्चों को जनजातीय कला की सूक्ष्म बारीकियों से परिचित कराया, जिससे बच्चों को भारतीय आदिवासी संस्कृति की समृद्ध परंपरा को समझने का अवसर मिला। वहीं राजस्थान के प्रसिद्ध मोलेला मूर्तिकला कलाकार प्रशांतभाई ने अपनी अनूठी मूर्तिकला का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वारली कला के प्रख्यात कलाकार महेशभाई ने भी हजारों बच्चों को इस प्राचीन कला की तकनीकों से अवगत कराया, जिससे बच्चों की रचनात्मक क्षमता को नई दिशा मिली।

13 फरवरी को शहर के विभिन्न स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के चेहरों पर उत्साह, जिज्ञासा और सीखने की ललक साफ दिखाई दे रही थी। पद्मश्री कलाकारों से सीधे मार्गदर्शन प्राप्त करना उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। इस अवसर ने बच्चों को न केवल कला सीखने का अवसर दिया, बल्कि उनके भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने और उसे विकसित करने की प्रेरणा भी दी। स्थानीय कलाकारों द्वारा आयोजित कला प्रदर्शनी भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण बनी, जहां विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, मूर्तियां और हस्तशिल्प वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। इन कलाकृतियों ने भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

इस आयोजन का सबसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण 14 फरवरी को आया, जब हजारों लोक कलाकार एक ही मंच पर एकत्रित हुए और उन्होंने एक साथ लोक नृत्य और लोक कला की प्रस्तुति दी। यह दृश्य अत्यंत भव्य और भावनात्मक था। कलाकारों की ऊर्जा, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ने पूरे वातावरण को जीवंत और उत्सवमय बना दिया। इस अद्वितीय उपलब्धि को मान्यता देने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि विशेष रूप से सूरत पहुंचे और आयोजकों को आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रदान किया। यह क्षण न केवल आयोजकों के लिए, बल्कि पूरे सूरत शहर के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया।

यह उपलब्धि सूरत के सांस्कृतिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। जिस शहर को अब तक मुख्य रूप से उद्योग और व्यापार के लिए जाना जाता था, वह अब कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब प्रशासन, कलाकार और समाज मिलकर प्रयास करते हैं, तो वे न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान बना सकते हैं। इस भव्य आयोजन ने यह संदेश दिया कि भारतीय कला और संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा भी है। यह आयोजन सूरत के लिए एक नई शुरुआत है, जो आने वाले समय में इस शहर को कला और संस्कृति के वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। सूरत अब केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गौरव और रचनात्मकता का भी उज्ज्वल केंद्र बनकर उभर रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।